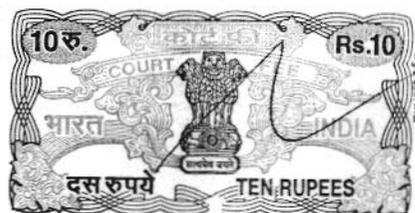


न्यायालय में प्रोमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर १ मध्य- प्रदेश १

खण्डपोठ- रोवा १ १० प्र० १



शिवप्रसाद तनय पचई कहार, साकिन- खुटार,

तहसील- मानपुर जिला- उमरिया १ १० प्र० १ ---- निगरानी कर्ता/आवेदक

ब नाम

१० प्र० शासन राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर

उमरिया, जिला- उमरिया १ १० प्र० १ ----- अनावेदक/उत्तरदाता

राजस्व निगरानी-

विरुद्ध निर्णय न्यायालय अपर कलेक्टर जिला उमरिया १ १० प्र० १ ब सिलसिले रा. प्र. क्रं. - ०५१ वा निगरानी / २०११-१२ १ कलेक्टर जिला- उमरिया का प्र. क्रं. १५३/१९४४/०९-१० आदेश दि०- ३०. ११. २०११ जिसके द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार मानपुर के रा. प्र. क्रं. - १९४/१९४४/८७-८८ में पारित आदेश दि०- १५. १०. ८८ को निरस्त किया गया है  
-----  
निगरानी अंतर्गत धारा- ५० म. प्र. भू. रा. सं.  
-----

मान्यवर,

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, कि मौजा-खुटार स्थित आराजी खारा नं. - १८८ रकबा २.०२३ हे० का भूमिस्वामी अधिकार म. प्र. ग्रामों की देखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना विशेष उपबंध अधि० १९८४ के अंतर्गत विधि अनुसार संपूर्ण प्रक्रियाओं को अपनाते हुए निगरानीकर्ता को भूमिहीन होने के कारण प्रदाय किया गया था उक्त भूमि पर किसी प्रकार के झाड़, जंगल आदि नहीं है और न ही भूमि किसी निस्तार प्रयोजन की रही है ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति न होने से अनापत्ति

प्रमाण पत्र दिया गया था नही ही किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई

५९३

R 573-11/12

अधिवक्ता श्री सज्जनी कुमारी  
सोनी द्वारा उत्तर  
Amul  
27/07/2012

7-3-12

Amul  
27/2/12

2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग.-573-दो/2012

जिला-उमरिया

शिवप्रसाद कहार विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-01-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री अंजनी कुमार सोनी उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा अपर कलेक्टर उमरिया जिला- उमरिया के प्रकरण क्रमांक- 05/स्व.निगरानी/2011-12 एवं कलेक्टर उमरिया के प्रकरण क्रमांक- 95/अ-19(4)/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 30-11-2011 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 27-02-2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।</p> <p>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार -</p> <p>“1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।”</p> <p>4. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय</p>	

hari  
22/01/19

3

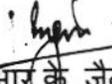
प्रकरण क्रमांक- निग.-573-दो/2012  
शिवप्रसाद कहार विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन

में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 28-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त शहडोल के न्यायालय में भेजा जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

  
(आर.के. जैन) 22/01/19  
सदस्य